भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 746

24 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवास निर्माण

746. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत अब तक कितने आवास निर्मित किए गए हैं और महिलाओं एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों के लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा शहरी स्वच्छता मिशन के अंतर्गत किसी भी शहर में अपशिष्ट जल प्रबंधन और स्वैच्छिक शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी नई तकनीक लागू की गई है और इस संबंध में ऐसी तकनीक का प्रभाव क्या है;

(ग) मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसी प्रमुख स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत नागरिकों को कौन-कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं;

(घ) क्या योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर हो रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शहरी क्षेत्रों में मेट्रो, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) और ई-बाइक जैसी सतत गतिशीलता सेवाओं के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में हाल ही में कितना निवेश किया गया है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए योजना की अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है तथा देश भर के शहरी क्षेत्रों में इसके

कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास का निर्माण किया, खरीदा और उन्हें किराये पर लिया जा सके। चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 7.09 लाख आवासों सहित पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल 119.25 लाख आवासों को स्वीकृत किया है। 14.07.2025 की स्थिति के अनुसार अब तक, देश भर में 112.81 लाख आवास निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 93.60 लाख आवास बनकर पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और महिला लाभार्थियों के लिए क्रमशः कुल 46 लाख और 93 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं।

(ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) शुरू किया है। इस मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शौचालयों (आईएचएचएल, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय, आकांक्षा के अनुरूप शौचालय और मूत्रालय) के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एसबीएम-यू 2.0 में एक नया घटक अर्थात् प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) भी शामिल है, जिसके अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए केंद्रीय सहायता जारी की जाती है:

- सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी)/एसटीपी-सह-एफएसटीपी की स्थापना
- एसटीपी तक पम्पिंग स्टेशनों और पम्पिंग मेन/ग्रेविटी मेन उपलब्ध कराने के साथ-साथ इंटरसेप्शन और डायवर्जन (आई एंड डी) संरचनाएं बिछाना
- पर्याप्त संख्या में सेप्टिक टैंक डिस्लजिंग उपकरणों की खरीद
- एसटीपी और संबद्ध उपकरणों के परिचालन चरण के दौरान दक्षता मापदंडों की वास्तविक समय निगरानी के लिए डिजिटल (आईटी सक्षम) उपकरणों की व्यवस्था।

(ग) और (घ): एससीएम ने 100 शहरों में रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास और ग्रीनफील्ड विकास के माध्यम से क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें जयपुर स्मार्ट सिटी, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) की ठाणे और कल्याण-डोम्बीवली स्मार्ट सिटीज और कोलकाता महानगर क्षेत्र की न्यू टाउन कोलकाता स्मार्ट सिटी में शुरू की गई परियोजनाएं शामिल हैं। इन चार शहरों की परियोजनाओं की शहर-वार स्थिति अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ड.): वर्तमान में, देश भर के 24 शहरों में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) सहित लगभग 1,036 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क चालू है। मेट्रो रेल नेटवर्क का शहर-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने पूर्ववर्ती जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है, जिसका वित्तपोषण वर्ष 2017 तक किया गया था। इसके अतिरिक्त, स्थायी गतिशीलता सेवाओं का विस्तार करने के लिए भारत सरकार ने 16 अगस्त 2023 को 'पीएम-ई-बस सेवा योजना' शुरू की, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाकर शहरी बस संचालन को बढ़ावा देना है।

*****

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 746 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

कल्याण-डोम्बीवली, ठाणे, जयपुर और न्यू टाउन कोलकाता शहरों की परियोजनाओं की शहर-वार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

स्मार्ट सिटी	कुल परियोजनाएं		पूर्ण परियोजनाएं		जारी परियोजनाएं	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
कल्याण-डोम्बीवली	19	1,244.58	16	721.13	3	523.45
ठाणे	52	1,712.18	50	1,402.16	2	310.02
जयपुर	170	2,545.38	166	2,403.83	4	141.55
न्यू टाउन कोलकाता	226	1,460.08	223	1,424.01	3	36.07

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 746 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

मेट्रो रेल नेटवर्क का शहर-वार विवरण

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**शहर**	**परिचालन लंबाई (किमी)**
1.	दिल्ली और एनसीआर	दिल्ली	395.817
2.		नोएडा	
3.		गाजियाबाद	
4.		फरीदाबाद	
5.		बल्लभगढ़	
6.		बहादुरगढ़	
7.		ग्रेटर नोएडा	
8.		गुरुग्राम	
9.		दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस	55
उप-योग (दिल्ली और एनसीआर)			**450.817**
10.	कर्नाटक	बैंगलोर	76.95
11।	तेलंगाना	हैदराबाद	69
12.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	59.37
13.	तमिलनाडु	चेन्नई	54.245
14.	राजस्थान	जयपुर	12.1
15.	केरल	कोच्चि	28.48

16.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	22.878
17.		कानपुर	15.12
18.		आगरा	6
उप-योग (उत्तर प्रदेश)			**43.99**
19.	महारष्ट्र	मुंबई	98.63
20.		नागपुर	40.022
21.		पुणे	33.23
उप-योग (महाराष्ट्र)			**171.882**
22.	गुजरात	अहमदाबाद	40
23.		गांधी नगर	22.7
उप-योग (गुजरात)			**62.7**
24.	मध्य प्रेदश	इंदौर	6.2
कुल			**1,035.74**